

# मूक पत्रिका

## निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष – 02      अंक – 284    बेमेतरा, बुधवार 10 जून 2026      रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित      कुल पेज – 08      मूल्य – 5 रुपये      डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

### संक्षिप्त समाचार

**झारखंड के गठन में भाजपा ने संघर्ष किया, अब राज्य के विकास पर काम कर रही पार्टी**

**रांची।** भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिवसीय संगठनात्मक दौर पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के गठन में भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया और उम्मीद का माहौल है। एक-एक कार्यकर्ता संकल्पित होकर भाजपा के कमल को फिर से झारखंड की भूमि पर मजबूती से खड़ा करने के लिए तैयार है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नितिन नवीन के झारखंड दौर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में उत्साह है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना बड़े ही गर्व की बात होती है। नितिन नवीन से पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला है। विकसित भारत 2047 पर हम काम कर रहे हैं। नितिन नवीन का यहां दो दिन का प्रवास था, निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है।

**भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज से परिचालन शुरू**

**भागलपुर।** बिहार के भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर फिर से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। फिलहाल छोटे वाहनों का परिचालन इस पल से प्रारंभ किया गया है। तीन मई की रात को पुल का एक स्लैब नदी में गिर गया था, जिसके बाद से इस सेतु पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप पड़ा था। शनिवार को जिला प्रशासन और विशेषज्ञों की देखरेख में यहां बनाए गए नए बेली ब्रिज का सुरक्षा द्रव्यल पूरी तरह सफल रहा था। इसके बाद जिला अधिकारी और पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया और परिचालन शुरू करने के लिए हरी झंडी दी थी। वर्तमान समय में इस सेतु पर ट्रक, बस, हाईवा के परिचालन की अनुमति नहीं मिली है। बेली ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क चौधरी ने आम लोगों से किया वादा पूरा किया।

**झारखंड से आमों का निर्यात शुरू, पहली खेप यूनाइटेड किंगडम भेजी गई**

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास कर रही है। इसी क्रम झारखंड राज्य के आमों का निर्यात शुरू किया गया है और पहली खेप को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से दी गई। इसे स्थानीय सामान के विदेशों में जाने का शानदार उदाहरण बताते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि झारखंड के सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आमपाली आम यूनाइटेड किंगडम पहुंचने वाले हैं। एपीडा के निरंतर प्रयासों से किसानों को बेहतर मूल्य, महिलाओं को नई पहचान और भारत के कृषि निर्यात को नई गति मिल रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने राज्य से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताजे आमों की पहली वाणिज्यिक खेप को हरी झंडी दिखाकर 4 जून 2026 को कोलकाता से रवाना किया।

साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर

# कृषक उन्नति योजना नए स्वरूप में होगी लागू-मुख्यमंत्री साय.....

रायपुर। संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, ऊर्जा, परिवहन, खनिज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी देने के साथ ही खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को भी स्वीकृति दी। इसके अलावा प्रदेश में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, योग विषय के प्रशासनिक पुनर्गठन और खनिज परिवहन व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने जैसे अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। सरकार का मानना है कि इस कदम से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा। साथ ही कंपनी की वित्तीय क्षमता, पारदर्शिता और संसाधन जुटाने की क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और धान पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। नई व्यवस्था के तहत धान के स्थान पर अन्य कृषक फसलें लेने वाले किसानों तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति-एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन



खनिज परिवहन में आरएफआईडी और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य होगी। साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। भंडारण अनुज्ञापत्रधारियों से वसूल जाने वाले भंडारण शुल्क और सिवियोरिटी डिपॉजिट में वृद्धि की गई है। इसके अलावा ईज ऑफडूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसधारकों को अतिरिक्त भूमि स्वीकृति तथा दो भंडारण लाइसेंसों के एकीकरण का प्रावधान भी लागू किया गया है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।

और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश में वैकल्पिक फसलों का रकबा बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता के साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र हितग्राहियों को चना वितरण को निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक चना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 0.25 प्रतिशत या उससे कम सर्विस चार्ज पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था की अवधि अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह के लिए बढ़ाने का अनुमोदन भी किया गया है। इससे खाद्य एवं

पोषण सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को चना वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा। मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि योग आयुष्य प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। और इससे संबंधित शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का बेहतर संचालन चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा सकेगा। इस निर्णय से योग आधारित शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों में बेहतर समन्वय स्थापित होगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने पेमेंट सिक्क्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के तहत डायरेक्ट डेबिट मॉडेल की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति दी है।

**मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं पर बोले सीएम साय: ‘यह सिर्फ अटकलें, किसी भी बात पर लगाए जा सकते हैं कयास**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल की चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें केवल कयासों पर आधारित हैं और किसी भी विषय को लेकर अटकलें लगाई जा सकती हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्तावित दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि उनका दौरा मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव या फेरबदल से जुड़ा हो सकता है। इसे लेकर लगातार अटकलों का दौर जारी था। इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि उनके दिल्ली दौरे का मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली नीति आयोग की बैठक और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं।

**वयों तेज हुई मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा?**

राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा पिछले कुछ दिनों से इसलि तेज हो गई थी क्योंकि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को इससे जोड़कर देखा जाने लगा। भाजपा संगठन और सरकार से जुड़े नेताओं की गतिविधियों के बीच राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जाने लगे कि सरकार में कुछ बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार के गठन को काफ़ी समय बीत जाने के बाद समय-समय पर विभागों में फेरबदल और राजनीतिक व क्षेत्रीय संतुलन को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। कुछ मंत्रियों के कामकाज और संगठनात्मक समीकरणों को लेकर भी अटकलें का दौर जारी था। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर चल रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लगने की संभावना है। उन्होंने साफ़कर दिया है कि उनका दिल्ली दौरा पूरी तरह से निर्धारित सरकारी और संगठनात्मक बैठकों के लिए है।

गलती से रह हुआ मीनाक्षी का नामांकन

# एमपी में कांग्रेस चित्त तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा

**नई दिल्ली।** मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रह कर दिया गया है। नामांकन पत्र में एक लंबित न्यायालयीन मामले की जानकारी छिपाने के आरोप पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच में नामांकन निरस्त कर दिया गया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रह होने के साथ ही राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत तय हो गई है। भाजपा ने तर्हण चुस, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक प्रकरण का उल्लेख नामांकन पत्र में नहीं किया। इसी आधार पर आपत्ति दाखिल की गई थी। वहीं कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक साजिश बताते हुए विरोध दर्ज कराया और विधानसभा परिसर में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस फैसले के बाद राज्यसभा चुनाव में मतदान की नौबत नहीं आएगी



और भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा पहुंचेंगे। इसे मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा की बड़ी रणनीतिक जीत और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस नेता उमंग सिंधार ने कहा कि एक गांधीवादी नारी से डर गई भाजपा। कांग्रेस की जीत और एक ईमानदार महिला प्रत्याशी की बढ़ती स्वीकार्यता से घबराई भाजपा का असली चेहरा आज मध्यप्रदेश विधानसभा में बेनकाब हो गया। जब कांग्रेस की जीत स्पष्ट दिखाई दे रही है, तब भाजपा हर प्रकार के साम, दाम, दंड, भेद का सहारा लेकर साजिश बताते हुए विरोध दर्ज कराया और विधानसभा परिसर में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस फैसले के बाद राज्यसभा चुनाव में मतदान की नौबत नहीं आएगी कोशिश की।

### बीजेपी ने क्या कहा

भाजपा की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार के लिए अपने खिलाफलंबित मामलों की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। इसी आधार पर भाजपा ने नामांकन के खिलाफआपत्ति दर्ज की थी। संकेत गुप्ता ने यह भी दावा किया कि संपत्ति से जुड़े विवरणों में भी विरोधाभास पाया गया, जिसे भाजपा ने अपनी आपत्ति का हिस्सा बनाया था। वहीं कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक साजिश बताते हुए विरोध दर्ज कराया और विधानसभा परिसर में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस फैसले के बाद राज्यसभा चुनाव में मतदान की नौबत नहीं आएगी।

सोनिया गांधी से मिलने पहुंचीं ममता

# टीएमसी के टूट के बीच आगे की रणनीति पर चर्चा की गई

नई दिल्ली/ एजेंसी

विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में एकजुटता और बेहतर समन्वय का संदेश देने के ठीक एक दिन बाद मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। यह महत्वपूर्ण बैठक सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर आयोजित हुई। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच इंडिया गठबंधन की भविष्य की दिशा, विपक्षी दलों के बीच ताजमेल मजबूत करने और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तृत



चर्चा हो सकती है। इसके अलावा, हाल के चुनावी झटकों के बाद टीएमसी में उभरे असंतोष और नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटनाओं पर भी बातचीत होने की संभावना बताई जा रही है। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब तृणमूल कांग्रेस संगठनात्मक चुनौतियों और आंतरिक खींचतान का सामना कर

रही है। पार्टी के कुछ सांसदों द्वारा अलग राह अपनाने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जाने की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात को विपक्षी राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोमवार को इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात का विषय बनी थी। बैठक शुरू होने से पहले सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी का बेहद आत्मीय अंदाज में स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई गर्मजोशी भरी बातचीत और सौहार्दपूर्ण मुलाकात ने विपक्षी खेमे में नए राजनीतिक संकेतों को लेकर अटकलों का दौर तेज कर दिया।

एनडीए सरकार के 12 साल

# पीएम मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड,सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश आजाद भारत के सबसे लंबे कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं. उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं. उन्होंने पूर्व पीएम पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. 9 जून 2024 को ही उन्होंने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में पीएम पद की शपथ ली थी और उनके सत्ता में रहने के 12 साल भी आज पूरे हो रहे हैं. पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज 9 जून 2026 तक उनके की शपथ ली थी. नेहरू लगातार

हैं. अब वो भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं. इस उपलब्धि पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 10 जून को बैठक होगी और इसमें एकजुटता दिखाने के साथ शक्ति प्रदर्शन होगा. इस बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू एक प्रस्ताव रखेंगे. अन्य सहयोगी दलों के नेता प्रस्ताव का समर्थन करेंगे प्रस्ताव में बतौर प्रधानमंत्री पिछले बारह साल की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा. बता दें इससे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 13 मई 1952 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. नेहरू लगातार



4397 दिन यानी 12 साल 14 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे. पीएम मोदी ने 9 जून को सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया. निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 4398 दिन यानी 12 साल 15 दिन

पूरे कर लिए हैं. नेहरू हालांकि 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने थे लेकिन 1952 में लोकसभा चुनाव के पहले तक वो पांच साल अंतरिम सरकार के प्रमुख थे. नेहरू तब तक चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बने थे. नेहरू 1947 से 27 मई 1964

तक प्रधानमंत्री पद पर रहे. ऐसे में नेहरू का पूरा टाइम तो 6130 दिन होता है. लेकिन इसमें से करीब 5 साल वो अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री रहे. इससे पहले पीएम मोदी ने 25 जुलाई 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगातार 4077 दिनों के प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था. पीएम मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले पहले गैर कांग्रेसी सरकार की भी हैं. वो गैर कांग्रेसी सरकार के ऐसे पहले नेता हैं, जिन्होंने लगातार दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और आम तौर पर एन एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं.













# संपादकीय

देश में यह एक नई तस्वीर बन रही है कि आर्थिक असुखा और बदहाली की स्थिति लोगों के मनोविज्ञान पर गहरा और घातक असर डाल रही है।सवाल है कि क्या केवल सख्ती के दावे और हिदायतों के दम पर राज्य में अपराध और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर काबू पाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में हाल में हत्या की कई घटनाओं से साफ है कि अपराध पर काबू करने के सरकारी दावों के बरक्स हकीकत क्या है। ऐसा लगता है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य की सरकार और पुलिस बेफिक्र हैं और दूसरी ओर अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा

रहा है। यह बेवजह नहीं है कि हत्या की लगातार कई वारदातों के बाद विपक्षी दलों की ओर से सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाने लगा है।दरअसल, बीते कुछ दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में एशियाई खेलों के लिए चुने गए एक पैग-एथलीट और एक राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी महिला खिलाड़ी सहित हत्या की अन्य घटनाओं के बाद सरकार इस बात के लिए आलोचना के कठघरे में है कि क्या राज्य की कानून-व्यवस्था ठप हो चुकी है।अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हाल में पिछले कुछ समय से लगातार बड़ी आपराधिक घटनाओं की वजह से खुद मुख्यमंत्री योगी के भीतर काफी नाराजगी देखी

गई और उन्होंने ज्यादा अपराध दर वाले जिलों के पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी।सवाल है कि क्या केवल सख्ती के दावे और हिदायतों के दम पर राज्य में अपराध और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर काबू पाया जा सकता है। अगर ऐसा संभव हो पाता, तो आज राज्य सरकार जघन्य अपराधों में तेज बढ़ोतरी के लिए खुद को आलोचना के घेरे में खड़ा नहीं पाती। जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब भाजपा का वादा यही था कि वह राज्य को अपराध और अपराधियों से मुक्त कराएगी।अपराधियों पर काबू पाने के मकसद से की गई कुछ फौरी सख्ती और

कार्रवाइयों से ऐसा लगा भी। मगर हत्या या अन्य किसी जघन्य अपराध के आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के कुछ मामलों में पुलिस के रवैये पर सवाल भी उठे। आज एक संसारंतर सच यह भी है कि आपराधिक मानसिकता के लोग बेधड़क सामान्य से लेकर जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और अपराध के खात्मे का दावा करने वाली सरकार अपराधियों को रोक पाने में नाकाम दिख रही है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के भीतर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। अपराध के बेलगाम होते जाने के बीच अब ऐसी घटनाएं भी

सामने आ रही हैं, जिनमें हत्या की वजहें हैरान करती हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की एक कबड्डी खिलाड़ी की हत्या सिर्फ 3,600 रुपये के उधार की वजह से कर देने की खबर आई। इस घटना में भी पहला सवाल यही है कि आरोपी के भीतर आखिर क्यों पुलिस और कानूनी कार्रवाई का कोई खौफ नहीं था।दूसरे, कोई व्यक्ति अपने लिए तीन-चार हजार रुपये को इतनी बड़ी रकम कैसे मान लेता है कि वह उसके लिए किसी की हत्या कर दे। उत्तर प्रदेश की इस घटना के अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं, जिनमें

दो-चार या पांच सौ रुपये जैसी मामूली रकम के लिए किसी की जान ले ली जा रही है।क्या देश में यह एक नई तस्वीर बन रही है कि आर्थिक असुरक्षा और बदहाली की स्थिति लोगों के मनोविज्ञान पर गहरा और घातक असर डाल रही है? जाहिर है, आदतन या सुविधा से अपराध करने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ-साथ सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों के जघन्य अपराधों को अंजाम देने की परिस्थितियों और वजहों पर विचार करना वक्त की जरूरत है। बिना जड़ पर प्रहार किए अपराध पर पूरी तरह काबू पाना एक चुनौती बनी रहेगी।

सीबीआई की जांच और संसदीय समिति की पूछताछ में यह संकेत मिले हैं कि प्रश्नपत्र तैयार करने और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े कुछ अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर चुनिंदा छात्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने का काम किया। यदि ये आरोप सही हैं तो यह केवल ऋष्टाचार नहीं बल्कि संस्थागत विश्वासघात है। भारत में परीक्षा अब केवल उद्योगता का आकलन नहीं रह गई है बल्कि यह करोड़ों सपनों की निर्णायक कसौटी बन चुकी है लेकिन जब यही कसौटी बार-बार संदिग्ध हो जाए, जब मेहनत और ईमानदारी की जगह ‘जुगाड़’ और ‘माफिया नेटवर्क’ हावी हो जाएं, तब यह केवल परीक्षा का संकट नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य का संकट बन जाता है।

# टूटते भरोसे के वेंटिलेटर पर देश की परीक्षा व्यवस्था

योगेश कुमार गोयल

पेपर लीक के चलते नीट-यूजी 2026 परीक्षा का रद्द होना, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन माफिक (ओएसएम) प्रणाली पर उठे गंभीर सवाल और एसएससी जीडी परीक्षा में धांधली, ये घटनाएं मिलकर यह साबित करती हैं कि भारत की परीक्षा प्रणाली अब गहरे संस्थागत संकट में फंस चुकी है और भारत की परीक्षा प्रणाली अब वेंटिलेटर पर है। नीट-यूजी 2026 का घटनाक्रम तो इस विफलता की सबसे भयावह तस्वीर पेश करता है। लगभग 22.79 लाख छात्रों की मेहनत, उनके परिवारों के त्याग और वर्षों की तैयारी एक झटके में शून्य हो गई। यह केवल एक परीक्षा का रद्द होना नहीं था बल्कि उस विश्वास का टूटना था, जिस पर पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि इस बार मामला केवल बाहरी गिरोंहों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जांच में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीई) के भीतर तक मिलीभगत के आरोप सामने आए।

सीबीआई की जांच और संसदीय समिति की पूछताछ में यह संकेत मिले हैं कि प्रश्नपत्र तैयार करने और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े कुछ अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर चुनिंदा छात्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने का काम किया। यदि ये आरोप सही हैं तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि संस्थागत विश्वासघात है। जिस संस्था को निष्पक्षता की गारंटी देनी थी, वही यदि धांधली का हिस्सा बन जाए तो पूरी व्यवस्था का नैतिक आधार ही खत्म हो जाता है। नीट पेपर लीक की प्रकृति भी सामान्य नहीं थी। ‘गैस पेपर’ के नाम पर लगभग 150 से अधिक प्रश्नों का हूबहू मिल जाना, परीक्षा से पहले 600 अंकों तक के सवालों का प्रसार, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्मस पर खुलेआम प्रश्नपत्र का घुसना, ये सब किसी संयोग का परिणाम नहीं हो सकते। यह एक संघटित, बहुस्तरीय और तकनीकी रूप से सक्षम नेटवर्क का संकेत है, जो परीक्षा प्रणाली की हर कमजोर कड़ी को भेद चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 में पेपर लीक के बाद भी कोई ठोस सुधार क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों, जांच समितियों और सिफारिशों के बावजूद 2026 में स्थिति और बदतर कैसे हो गई? इसका सीधा अर्थ है कि समस्या तकनीकी कम और इच्छाशक्ति की अधिक है।

भारत की परीक्षा प्रणाली का ढांचा ही कई स्तरों पर कमजोर है। प्रश्नपत्रों की छपाई से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया में निजी एजेंसियों और आउटसोर्स



कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रहती है। यही वह जगह है, जहां से माफिया नेटवर्क अपनी जुड़े जाता है। जब प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले ही स्कैन होकर डिजिटल रूप में फैल सकता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि सुरक्षा तंत्र केवल कामाजों पर मजबूत है, जमीन पर नहीं। दूसरी ओर, कोचिंग उद्योग का अनियंत्रित विस्तार इस संकट को और गहरा कर रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं अब हजारों करोड़ रुपये का बाजार बन चुकी हैं। इस बाजार में ‘सफलता’ एक उत्पाद है, जिसे खरीदने के लिए छात्र और अभिभावक किसी भी हद तक जाने को मजबूर हैं। इसी मानसिकता का फायदा उठाकर एजुकेशन माफिया ‘सीक्रेट पेपर’, ‘100 प्रतिशत सलैक्शन गारंटी’ और ‘इनसाइडर एक्सेस’ जैसे झूठे वादों के जरिए पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है।

यदि नीट प्रकरण परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है तो सीबीएसई का ओएसएम विवाद मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर चोट करता है। डिजिटल मूल्यांकन को पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया था लेकिन इसके परिणाम उल्टे दिखाई दिए। काम प्रतिशत में गिरावट, मेधावी छात्रों को अपेक्षा से कम अंक मिलना और स्कैन की गई कॉपियों में भारी गड़बड़ियां, ये सब इस बात के संकेत हैं कि तकनीक को बिना पर्याप्त तैयारी और परीक्षण के लागू किया गया। कई छात्रों ने शिकायत की कि उनकी कॉपियां धुंधली थीं, कुछ को गलत उत्तर पुस्तिका मिली और कुछ मामलों में तो पूरी कॉपी ही किसी और की थी। यह स्थिति केवल तकनीकी त्रुटि नहीं मानी जा सकती बल्कि यह सरासर गंभीर ऋशसनिक लापरवाही है। यदि एक छात्र की

मेहनत को किसी दूसरे की कॉपी से बदल दिया जाए तो यह केवल गलती नहीं है बल्कि उस छात्र के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। शिक्षा मंत्रालय और बोर्ड भले ही इन खामियों को सीमित मामलों तक बताकर पछड़ा झाड़ों की कोशिश करें लेकिन छात्रों में बढ़ता असंतोष इस बात का प्रमाण है कि समस्या व्यापक है।

तीसरी बड़ी घटना, एसएससी कॉन्टेबल जीडी परीक्षा में धांधली, इस बात को और स्पष्ट करती है कि यह संकट किसी एक परीक्षा या संस्था तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में पेपर लीक, तकनीकी खराबी और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ग्रेटर नोएडा में यूपी एसटीएफ द्वारा पकड़े गए रैकेट ने इस धांधली के आधुनिक रूप को उजागर किया। प्रांक्सि सर्वर, स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स और डेमी फेडिडेयट्स के जरिए परीक्षा में हेफरेफ किया जा रहा था। यह पारंपरिक नकल या पेपर लीक से कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि इसमें तकनीक का इस्तेमाल कर पूरी प्रणाली को भीतर से हैक किया जा रहा है। इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें तो एक भयावह तस्वीर उभरती है, एक ऐसी व्यवस्था, जहां प्रश्नपत्र सुरक्षित नहीं, मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं और परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। सबसे अधिक पीड़ित वह छात्र हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों छात्र, जिनके माता-पिता ने कर्ज लेकर या जमीन गिरवी रखकर उहड़ें कोचिंग दिलाई, आज सबसे ज्यादा निराश हैं। एक परीक्षा रद्द होने का मतलब केवल दोबारा परीक्षा देना नहीं होता बल्कि यह मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और आत्मविश्वास के टूटने का कारण बनता है।

इस पूरे संकट का एक और खतरनाक पहलू है

व्यवस्था के प्रति बढ़ता अविश्वास। जब छात्र यह मानने लगे कि सफलता मेहनत से नहीं बल्कि ‘सेटिंग’ से मिलती है तो यह केवल शिक्षा का नहीं बल्कि सामाजिक नैतिकता का भी पतन है। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? क्या हर बार जांच, गिरफ्तारी और बयानबाजी से काम चल जाएगा? स्पष्ट है कि नहीं। सबसे पहले परीक्षा प्रणाली में पूर्ण डिजिटल और एन्क्रिप्टेड मॉडल लागू करना होगा। प्रश्नपत्रों को परीक्षा से कुछ मिनट पहले तक सुरक्षित सर्वर में रखा जाए और सीधे केंद्रों पर डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाए। इससे छपाई और परिवहन से जुड़ी कमजोरियां समाप्त होंगी। दूसरा, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को सीमित करना होगा। सर्वेदनशील कार्यों में केवल प्रशिक्षित और जवाबदेह सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरा, पेपर लीक को संघटित आर्थिक अपराध घोषित कर इसके लिए गैर-जमानती कठोर कानून बनाए जाएं। जब तक अपराधियों को कठोर सजा नहीं मिलेगी, तब तक यह धंधा बंद नहीं होगा। चौथा, साइबर निगरानी को मजबूत करना होगा। टेलीग्राफ, डाक वेब और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्मस पर सक्रिय नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए विशेष एजेंसियां बनाई जानी चाहिए। पांचवां, तकनीक को लागू करने से पहले उसका व्यापक परीक्षण और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। सीबीएसई ओएसएम विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना तैयारी के लागू की गई तकनीक समाधान नहीं बल्कि नई समस्या बन सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति। जब तक सरकार इस समस्या को ‘राष्ट्रीय आपदा’ की तरह नहीं देखेगी, तब तक आधे-अधूरे समाधान ही सामने आएंगे। नीट-यूजी 2026, सीबीएसई ओएसएम विवाद और एसएससी परीक्षा धांधली, ये घटनाएं चेतावनी हैं। यदि अब भी कठोर और स्थायी सुधार नहीं किए गए तो आने वाले समय में हर परीक्षा संदेह के घेरे में होगी। तब सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होगी कि पेपर लीक हुआ बल्कि यह होगी कि देश के युवाओं का विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा। और जिस राष्ट्र के युवा ही अपनी व्यवस्था पर विश्वास खो दें, उसके भविष्य की नींव कितनी कमजोर हो जाती है, यह समझना मुश्किल नहीं है। (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और ‘सागर से अंतरिक्ष तक-भारत की रक्षा क्रांति’ सहित कई चर्चित पुस्तकों के लेखक हैं)

( इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं। )

## पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश से रक्षा संबंध बना रहा तुर्किये, भारत को दो तरफ से घेरने की रणनीति!

(नीरज कुमार दुबे)

तुर्किये ने साफ संकेत दे दिया है कि वह दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी केवल व्यापार या मानवीय सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहता। ढाका में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में रक्षा सहयोग, रक्षा उत्पादन, सामरिक साझेदारी और आर्थिक विस्तार पर जिस गंभीरता से चर्चा हुई, वह भारत के लिए साधारण घटना नहीं है।

दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीतिक बिसात पर अब एक नया और बेहद खतरनाक समीकरण तेजी से उभर रहा है। भारत विरोधी रवैये के लिए लंबे समय से चर्चित तुर्किये अब केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने बांग्लादेश के साथ भी अपने रक्षा और सामरिक रिश्तों को तेजी से विस्तार देना शुरू कर दिया है। ढाका पहुंचे तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने जिस तरह बांग्लादेश को दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया, उसने नई दिल्ली की चिंता और गहरा डर है। इस बयान को भारत के चारों ओर रणनीतिक दबाव बनाने की सुनियोजित चाल के रूप में देखा जा रहा है।

तुर्किये ने साफ संकेत दे दिया है कि वह दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी केवल व्यापार या मानवीय सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहता। ढाका में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में रक्षा सहयोग, रक्षा उत्पादन, सामरिक साझेदारी और आर्थिक विस्तार पर जिस गंभीरता से चर्चा हुई, वह भारत के लिए साधारण घटना नहीं है। बांग्लादेश ने तुर्किये को रक्षा सामग्री निर्माण में निवेश का खुला न्योता दिया है। दोनों देशों ने पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है। यह वही तुर्किये है जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर वर्षों तक भारत विरोधी मोर्चेबंदी की, कश्मीर मुद्दे पर खुलकर इस्लामाबाद का साथ दिया और इस्लामी सहयोग संगठन के मंचों पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया।

उधर, दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता यह है कि तुर्किये अब भारत के पड़ोसी मोर्चे पर पाकिस्तान और पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश के साथ समानांतर सामरिक रिश्ते बना रहा है। यह दो तरफा दबाव के रणनीति जैसी दिखाई देती है। पाकिस्तान पहले से ही तुर्किये के रक्षा उद्योग, ड्रोन तकनीक और सैन्य प्रशिक्षण का लाभ उठा रहा है। अब यदि वही ढांचा बांग्लादेश तक पहुंचता है, तो भारत के लिए सुरक्षा समीकरण और जटिल हो जाएंगे। खास तौर पर तब, जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार अपनी विदेश नीति को नए ढंग से गढ़ने के की कोशिश कर रही है।इसके अलावा, तुर्किये और पाकिस्तान भी तेजी से बढ़ रही हैं। दोनों देश व्यापार को तेरह अरब डॉलर से बढ़ाकर

बोस अरब डॉलर तक ले जाने की तैयारी में हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में तुर्किये को निवेश का निमंत्रण दिया गया है।

वस्त्र, दवा निर्माण, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। ढाका में अंतरराष्ट्रीय स्तर का असतुलन और नसिंग संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। यह साफ दिखाता है कि तुर्किये केवल सैन्य साझेदारी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव स्थापित करने की नीति पर काम कर रहा है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुर्किये दक्षिण एशिया में खुद को मुस्लिम दुनिया के प्रभावशाली संरक्षक के रूप में स्थापित करना चाहता है। रोहिंया मुद्दे पर उसकी सक्रियता, गाजा पर आक्रामक बयानबाजी और बांग्लादेश के साथ मानवीय सहयोग इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इसके पीछे छिपा बड़ा उद्देश्य क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार और भारत की सामरिक चुनौती को बढ़ाना है।वैसे तो तुर्किये लगातार यह कह रहा है कि वजह को उसके पाकिस्तान से रिश्तों की वजह से उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन असली सवाल भरोसे का है। राष्ट्रपति एर्दोआन कई बार खुलकर कश्मीर पर पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे चुके हैं। तुर्किये ने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा रिश्ते भी काफी मजबूत कर लिए हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्किये ने पाकिस्तान को रक्षा उपकरण और ड्रोन तक मुहैया कराए थे। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से आए जिन कई झूठों को मार गिराया था, उनमें तुर्किये में बने ड्रोन भी शामिल थे। ऐसे में तुर्किये का भारत से दोस्ती और संतुलन की बात करना नई दिल्ली को एक सौची समझी रणनीतिक चाल जैसा लगता है।यही वजह है कि भारत भी अब तुर्किये को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है।

दरअसल, भारत ने हाल के वर्षों में साइप्रस और ऑर्मिनिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को तेजी से मजबूत किया है। ऑर्मिनिया अब भारतीय हथियारों का बड़ा खरीदार बन चुका है। साइप्रस के साथ भी भारत रणनीतिक और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। यह सीधे-सीधे तुर्किये को संदेश है कि यदि अंकारा भारत के पड़ोस में दखल बढ़ाएगा, तो नई दिल्ली भी तुर्किये के सामरिक क्षेत्र में जवाबी दबाव बनाएगी। जिस तरह तुर्किये पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह भारत भी तुर्किये के विरोधी या प्रतिस्पर्धी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। यह नई शीर्ष प्रतिद्वंद्विता का संकेत है।

उधर, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की विदेश नीति भी इस समय भारत के लिए गहरा चिंता का विषय बनती जा रही है। भारत की ओर से सबसे पहले आधिकारिक यात्रा का निमंत्रण मिलने के बावजूद रहमान ने पहले मलेशिया और फिर चीन जाने का फैसला किया।

# तृणमूल कांग्रेस में टूट और ममता की बढ़ती चिन्ताएं

(ललित गर्ग)

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के समक्ष खड़ी चुनौतियों को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जब किसी दल का नेतृत्व स्वयं को संगठन और जनता से ऊपर मानने लगता है, तब असंतोष जन्म लेता है, कार्यकर्ता दूर होने लगते हैं और अंततः राजनीतिक आधार कमजोर पड़ने लगता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), जिसने पिछले डेढ़ दशक से बंगाल की राजनीति पर लगभग एकाधिकार स्थापित कर रखा था, आज आंतरिक असंतोष, नेतृत्व संबंधी प्रश्नों और जनविश्वास के संकट से जूझती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर असंतुष्ट नेताओं और विधायकों की गतिविधियों ने यह संकेत दिया है कि संगठनात्मक एकता में दरारे उभर रही हैं। यह स्थिति केवल किसी एक राजनीतिक दल का संकट नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में राजनीतिक मूल्यों, जनभावनाओं और नेतृत्व की भूमिका पर पुनर्विचार का अवसर भी है।

राजनीति में इतिहास बार-बार यह प्रमाणित करता रहा है कि जब भी सत्ता के साथ अहंकार जुड़ता है, जनता अंततः उसका उत्तर देती है। लोकतंत्र में जनता ही अंतिम निर्णायक होती है। चाहे वह इंदिरा गांधी का आपातकाल हो, पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन या दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अंत या फिर उत्तर प्रदेश एवं बिहार की अनेक राजनीतिक घटनाएं-हर जगह जनता ने यह संदेश दिया है कि सत्ता जनता की सेवा के लिए है, शासन के अहंकार के लिए नहीं।ममता बनर्जी को कभी संघर्षशील, जुझारू और जननेता के रूप में देखा जाता था। उन्होंने वामपंथी शासन के लंबे दौर को समाप्त कर बंगाल में परिवर्तन का नया अध्याय लिखा। किंतु समय के साथ उनकी राजनीति पर अहंकारवाद, व्यक्तिवाद और तुष्टिकरण के आरोप बढ़ते गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के भीतर निर्णय प्रक्रिया का अत्यधिक केंद्रीकरण और कुछ व्यक्तियों का बड़का प्रभाव अनेक वरिष्ठ नेताओं को असहज करता रहा है। यह कारण है कि समय-समय पर असंतोष के स्वर उभरते रहे हैं। राजनीतिक टिप्पणीकारों द्वारा प्रकाशित विश्लेषणों में भी यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि किसी दल में प्रचंड से अधिक व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाए, तो वहां असंतोष स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। हाल के घटनाक्रमों ने इस आशंका को और बल दिया है। जिस प्रकार पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता और विधायक नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि समस्या केवल व्यक्तियों की नहीं, बल्कि संगठनात्मक संस्कृति की भी है।

भारतीय राजनीति में हाल के वर्षों में आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। वर्ष 2013 से लेकर 2024 तक दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले कीर्तवीराल को जनता ने ईमानदार, पारदर्शी और वैकल्पिक राजनीति के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। लेकिन समय के साथ सत्ता का केंद्रीकरण, विरोधियों के प्रति असहिष्णुता, राजनीतिक



अहंकार और स्वयं को अजेय मान लेने की प्रवृत्ति उनके नेतृत्व पर हावी होती दिखाई दी। जनता ने देखा कि जो दल कभी राजनीतिक शुचित्व और नैतिकता की बात करता था, वह भी सत्ता के उसी मोह और व्यक्तिकेंद्रित राजनीति का शिकार होता जा रहा है, जिसके विरुद्ध उसने संघर्ष प्रारम्भ किया था। परिणामस्वरूप दिल्ली की राजनीति में उसका प्रभाव कमजोर हुआ और जनता ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि लोकतंत्र में कोई भी नेता अथवा दल जनता से बड़ा नहीं होता। यह घटना इस सत्य को पुनः स्थापित करती है कि जनता लंबे समय तक अहंकार, अतिशयोक्ति और आत्मगुंथता को स्वीकार नहीं करती।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के समक्ष खड़ी चुनौतियों को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जब किसी दल का नेतृत्व स्वयं को संगठन और जनता से ऊपर मानने लगता है, तब असंतोष जन्म लेता है, कार्यकर्ता दूर होने लगते हैं और अंततः राजनीतिक आधार कमजोर पड़ने लगता है। इतिहास बताता है कि लोकतंत्र में विनम्रता, संवाद, जनभावनाओं का सम्मान और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता ही स्थायी राजनीतिक सफलता की कुंजी हैं। किसी भी लोकतांत्रिक दल की शक्ति उसके विचार, संगठन और कार्यकर्ताओं में होती है, न कि केवल एक नेता में। जब

दल विचारधारा की बजाय व्यक्तिपूजा पर आधारित होने लगते हैं, तब उनका संकट निश्चित हो जाता है। भारतीय राजनीति में अनेक उदाहरण हैं जहाँ परिवारवाद ने दलों की जड़ों को कमजोर किया। महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पीछे भी नेतृत्व और उत्तराधिकार से जुड़े प्रश्न महत्वपूर्ण रहे। बंगाल में भी इसी प्रकार की चर्चाएँ समय-समय पर सामने आती रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के सामने दूसरा बड़ा संकट उसकी सार्वजनिक छवि का है। शिक्षक भर्ती, नगर निकायों तथा अन्य प्रशासनिक मामलों से जुड़े विवादों ने जनता के मन में अनेक प्रश्न खड़े किए हैं। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास होता है। यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही कम हो रही है, तो राजनीतिक नुकसान होना स्वाभाविक है।

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चल रही पहचान, नागरिकता, सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ से जुड़ी बहसों ने भी राजनीतिक वातावरण को प्रभावित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया। भाजपा का प्रकट रहा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए और किसी भी प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति अंततः समाज को विभाजित करती है। यही कारण है कि बंगाल में भाजपा ने अपनी राजनीतिक रणनीति को राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और सुशासन के मुद्दों पर केंद्रित किया। भाजपा की बंगाल यात्रा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अध्ययन का विषय है। कभी केवल दो सीटों तक सीमित रहने वाली पार्टी आज राज्य की सत्ता शक्ति बन चुकी है। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे वर्षों का संगठनात्मक विस्तार, बुध स्तर तक कार्यकर्ताओं का निर्माण, राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता तथा स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ने की रणनीति रही है। भाजपा ने बंगाल में यह संदेश देने का प्रयास किया कि वह केवल एक राजनीतिक विपक्ष नहीं, बल्कि वैचारिक विकल्प भी है। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि केवल राष्ट्रवाद या धार्मिक पहचान के आधार पर किसी दल की स्थायी

सफलता सुनिश्चित नहीं होती। लोकतंत्र में जनता विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी चाहती है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय भावना के साथ-साथ जनकल्याणकारी नीतियों को भी प्राथमिकता दे।

राष्ट्र और राजनीति का संबंध अत्यंत गहरा है। कोई भी राजनीतिक दल तभी दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकता है जब वह राष्ट्रहित, संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनभावनाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहे। यदि कोई दल ऐसे तत्वों का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है जो राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध हों, तो जनता धीरे-धीरे उससे दूरी बनाने लगती है। भारत की लोकतांत्रिक चेतना इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वह अंततः राष्ट्रहित और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करने वाले नेतृत्व को ही स्वीकार करती है। पश्चिम बंगाल का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य इसी सत्य की पुष्टि करता है। तृणमूल कांग्रेस के सामने चुनौती केवल बग़ायत या संगठनात्मक असंतोष नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास को पुनः अर्जित करने की भी है। यदि पार्टी अलमत्तमन करती है, संगठन को लोकतांत्रिक बनाती है, पारदर्शिता बढ़ाती है और जनभावनाओं को समझने का प्रयास करती है, तो वह अपनी स्थिति को पुनः मजबूत कर सकती है। लेकिन यदि अहंकार, व्यक्तिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति जारी रहती है, तो संकट और गहरा सकता है। यही लोकतंत्र का शाश्वत सत्य है और यही पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीति का सबसे बड़ा संकट भी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सत्ता स्थायी नहीं होती, किंतु मूल्य स्थायी होते हैं। राजनीतिक दल आते-जाते रहते हैं, लेकिन जनता की अपेक्षाएं और राष्ट्र की आवश्यकताएँ हमेशा बनी रहती हैं। जो दल इन अपेक्षाओं को समझते हैं, वे इतिहास बनाते हैं और जो इन्हें अनदेखा करते हैं, वे इतिहास बन जाते हैं। आज बंगाल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि तृणमूल कांग्रेस आत्मसुधार का मार्ग चुनती है या रास्तेभ्रष्ट पतन की ओर बढ़ती है। लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)















